

बेलसोनिका यूनियन रजिस्ट्रेशन रद्द करने के हिटलरी फरमान का पुरजोर विरोध ठेका मजदूर भी इंसान हैं, हुक्मत को समझना पड़ेगा

क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा

छुट्टी के दिन शनिवार 23 सितम्बर को, हरियाणा सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार सेक्टर 17, चंडीगढ़ स्थित अपने दफ्तर में हाजिर हुए, वह काम निवारण सरकार बहादुर को सूचित किया उसके बाद ही छुट्टी मनाई!! वह काम था मानेसर स्थित मारसी की सहायक कंपनी बेलसोनिका की मजदूर यूनियन 'बेलसोनिका ऑटो कंपनी ट्रेड यूनियन एम्प्लाइज यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 1983' को रद्द करना। ये काम एक दिन बाद सोमवार को भी तो हो सकता था उससे हरियाणा सरकार और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार पर कौन सी आफत आ जाती!! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। ये काम सोमवार तक का इंजार नहीं कर सकता था। इसे छुट्टी के उसी दिन, शनिवार को ही होना था 'संसद के विशेष सत्र स्टाइल' में!! कुछ काम हुक्मतों के लिए इतने अहम होते हैं, मैंचों के सवाल होते हैं सत्ता किसके हाथ है ये दिखाना होता है कि वे सिर्फ मुकम्मल ही नहीं किए जाते बल्कि एक विशिष्ट अंदाज में एक ठोस संदेश देते हुए किए जाते हैं। हरियाणा सरकार राज्य के सरमाएदार आकाओं को ये संदेश देना चाहती थी कि आप ही हमारे असली 'भाग्य विधाता', माई-बाप हो। आपके मुनाफे पर कोई आच आती हो तो हम छुट्टी क्या दिन-रात भी नहीं देखेंगे। एक दिन पर खड़े रहेंगे, हजूर!!

यूनियन रजिस्ट्रेशन रद्द करने के हुक्मनामे आर-1/2023/26878, दिनांक 23.09.2023 की प्रति क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के पास है। यूनियन का गुनाह: केशव राजपूत नाम के ठेका मजदूर को यूनियन का सदस्य बनाया। 5.09.22 को जारी हुए कारण बताओ नोटिस के जवाब में यूनियन ने 28.09.22 को लिखा कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का नियम 5, सेक्शन 6, यूनियन बनाने के अधिकार के मामले में स्थाई मजदूर और ठेका मजदूर में कोई भेद नहीं करता। ठेका मजदूर को भी यूनियन बनाने के अधिकार से महसूल नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार की आपत्ति; यूनियन ने नियम 5 के उक्त सेक्शन की कॉपी नथी नहीं की!! ये सेक्शन कहता है 'वह मजदूर जिसे कंपनी ने काम पर लगाया है यूनियन का सदस्य बन सकता है। इसमें ऐसा कहां लिखा है कि मजदूर और ठेका मजदूर संयुक्त रूप से यूनियन के सदस्य बन सकते हैं।' क्या कमाल का तरक्की भिड़ाया है रजिस्ट्रार ने!! 1926 में जब ट्रेड यूनियन कानून बना था तब दुनिया भर के सरमाएदार और उनके रजिस्ट्रार जैसे ताकेदार मजदूरों की संगठित क्रांतिकारी शक्ति से थर्हा रहे थे, क्योंकि रूस के मजदूर पूजी के इस घिनौने तंत्र को उखाड़कर फेंक चुके थे। उस वक्त उन्हें नहीं मालूम था कि पूजी की ये विवेली बेल फिर उग आएगी और मालिकों को 'ठेका प्रथा' के नाम पर मजदूरों का खन चूसने की खुली छूट मिलगी। इसीलिए ये भी कहां लिखा हुआ है कि ठेका मजदूर यूनियन के सदस्य नहीं बनेंग।

'ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियन अपने काम-काज करने के नियम बना सकती है। सदस्यता की पात्रता क्या होगी सदस्यता शुल्क क्या होगा ये तय कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को भी अपना पदाधिकारी चुन सकती है जो उस कंपनी में काम नहीं करता।' ये बातें खुद रजिस्ट्रार ने अपने हुक्मनामे में भी लिखी हैं लेकिन

चूंकि, 'ठेका मजदूर को सदस्य बनाया जा सकता है' ये कहां नहीं लिखा तो अपने ठेका मजदूर के शब्द राजपूत को सदस्य क्यों बनाया ये सवाल किया? ट्रेड यूनियन एक्ट कहता है 'उसी मजदूर को सदस्य बनाया जा सकता है जो कंपनी के लिए काम कर रहा हो।' तो फिर ठेका मजदूर क्या उसी कंपनी बेलसोनिका के लिए काम नहीं कर रहे? उनके उत्पाद को कौन हथियाता है? उन्हें मारुती को बेचकर मुनाफ़ा किसके ताकूत में जमा होता है?

'ट्रेड यूनियन एक्ट 1926' के कुल 12 पृष्ठों में कहीं एक बार भी 'ठेका मजदूर' शब्द नहीं आया। ऐसे में हर कारखानेदार ठेका मजदूरों के नाम पर जो भर्तीयां कर रहा है, ठेका मजदूरों को इंसान का दर्जा ही नहीं दे रहा, जब तक उसका दिल करता है उनसे काम लेता है, छुट्टियां नहीं देता, वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं देता, मेडिकल छुट्टियां, मातृत्व छुट्टियां नहीं देता, प्रोमोशन नहीं देता, पैशन नहीं देता, मौत हो जाने पर आस्त्रित को नोकरी, मुआवजा कुछ नहीं देता। ऐसा करने वाला हर मालिक ट्रेड यूनियन कानून ही नहीं देश के हर श्रम कानून, इसांक के नैसर्गिक कानून, जिंदा रहने के संवेदनिक अधिकार समेत क्या सभी कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा? एक छुट्टी को काम पर आकर उसकी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन क्यों रद्द नहीं कर डालते? रजिस्ट्रार को इन सवालों से कोई मतलब नहीं!!

रजिस्ट्रार अपने हुक्मनामे में आगे पृष्ठ 4 पर फरमाते हैं 'कानून कहता है कि केवल वे मजदूर ही यूनियन के सदस्य बन सकते हैं जिनके हित समान हैं।' अलग-अलग और बे-मेल हित वाले मजदूरों की एक यूनियन नहीं हो सकती...बेलसोनिका के मजदूरों पर बेलसोनिका की सेवा-शर्तें लागू होती हैं लेकिन ठेका मजदूरों पर ठेकेदार की सेवा शर्तें लागू होती हैं।' वाह जी वाह इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी!! बेलसोनिका के नियमित मजदूरों और ठेका मजदूरों के हित कैसे भिन्न हुए रजिस्ट्रार जी? हमारा तो कहना है कि बेलसोनिका मारसी, लखानी क्या किसी भी कंपनी के मजदूरों के हित भिन्न नहीं हैं। सारी दुनिया के मजदूरों के हित एक समान हैं। आपने वो नारा नहीं सुना 'दुनिया के मजदूरों का हो!' मालिकों के हित अलग-अलग होते हैं। वे एक दसरे के पेट पर पांव रखकर ऊपर जाते हैं एक-दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। और ये जो आखिरी वाक्य में आपने ठेका मजदूरों की बात जोड़ी है, वह ट्रेड यूनियन एक्ट में कहां लिखी है? क्या ये आपकी उपजाऊ खोपड़ी की उपज नहीं है??

विड्मना देखिए, रजिस्ट्रार ने अपने हुक्मनामे में 'एस्कोर्ट्स एम्प्लाइज यूनियन' मामले में चंडीगढ़ उच्च न्यायलय के आदेश का उल्लंघन किया है। आप और आपके आका कानून का भी समान नहीं करते सर। अगर करते होते तो बेलसोनिका यूनियन का ये मुहा भी तो उसी चंडीगढ़ उच्च न्यायलय में लंबित है जिसका जिक्र रजिस्ट्रार कर रहा है। अदालत का फैसला आने का भी सब नहीं हुआ!! 'मामला सब-ज्युडिस है' ये जुमला मजदूरों को धमकाने के लिए ही है क्या? अदालत का फैसला आने तक रुक जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ने वाला था!! 'दो संस्थानों के मजदूर एक यूनियन के सदस्य नहीं हो सकते। बेलसोनिका कंपनी और उसका ठेकेदार दो अलग-अलग संस्थान हैं ये कैसे सिद्ध



बेलसोनिका यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड मोहिन्दर कपूर (दाएं) महासचिव कॉमरेड अंजीत सिंह (बाएं)

कोर्ट 'बोकाजन सीमेंट कारपोरेशन एम्प्लाइज यूनियन' वाले मामले में ये फैसला सुना हो चुकी है कि किसे सदस्यता देना है और किस नहीं देना यूनियन का अधिकार है। इसमें कोई बाहरी दखलांदाजी नहीं होनी चाहिए। लैंकिन रजिस्ट्रार फिर भी दखलांदाजी करेंगे क्योंकि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं!! तब तो ये अदालतें बद कर दी जानी चाहिए। जो मालिक के मुंह से निकल गया वही कानून है, ऐसा फरमान जारी कर दिया जाना चाहिए। हुक्मतें लैंकिन वह भी नहीं करेंगी क्योंकि तब तो मजदूरों को ये समझ आ जाएगा कि न्याय पाने के लिए उन्हें क्या करना है। ऐसा तो सोचते ही मालिकों को पसीने छूटते हैं। मुगालता भी रहना चाहिए धुंधलका भी रहे जिससे आगे का रास्ता साफ नज़र ना आए!!

'यूनियन को, एक ही सांस में आग-बबूला और नरम नहीं होने दिया जा सकता।' आग-बबूला तो आप हो रहे हैं रजिस्ट्रार जी। मजदूरों की गर्मी आपने देखी ही कहां है अभी। मजदूर जिस दिन आग-बबूला होंगे उस दिन आप और आपका ये जर्जर तत्र, उन्हें नहीं रोक पाएंगा। मजदूर अगर एक हो गए जैसे कि इमकानात जर्जर आ रहे हैं तो, सदियों का पुराना हिसाब बराबर कर डालेंगे। मालिकों और उनके रांगबिरों ताबेदारों को सड़कों पर दौड़ा लेंगे और उस दिन मजदूर किसी रजिस्ट्रार से अनुमति नहीं लेंगे। फूर्सत मिले तो इतिहास पढ़िएगा। रजिस्ट्रार आगे फरमाते हैं; 'अदालत में मामला लंबित है', मात्र इतना कहने से वैधानिक सरकार को फैसला लेने से नहीं रोका जा सकता' तो फिर अदालत की अवमानना क्या होती है मिस्टर रजिस्ट्रार? सरकार वैधानिक है तो क्या अदालत अवैधानिक है?

करे।' यूनियन ने सदस्यता रद्द करने की धमकी वाले पत्र दिनांक 26.12.22 के जवाब में दिनांक 27.02.23 को अपने जवाब में अगर खुद ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए जान का उल्लंघन कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? रजिस्ट्रार द्वारा जारी लिखित दिशा-निर्देश का उल्लंघन कहां हुआ? रजिस्ट्रार ने छुट्टी के दिन यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का हुक्मनामा कहां इस दिन से जो जारी नहीं किया कि चंडीगढ़ उच्च न्यायलय मजदूरों के पक्ष में फैसला सुना सकता है? रजिस्ट्रार ने अपने दिशा-निर्देश में ये कहां लिखा है कि ठेका मजदूर करे।' यूनियन ने सदस्यता रद्द करने की धमकी वाले पत्र दिनांक 26.12.22 के जवाब में दिनांक 27.02.23 को अपने जवाब में अगर खुद ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए जान का उल्लंघन कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया?

मजदूरों को महीने की मजदूरी रु 50,000 रुपये की जगह, मात्र 12,000 रुपये देकर डबल काम लिया जाएगा कोई श्रम अधिकार नहीं दिया जाएगा इसीलिए तो मालिकों औ